RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 21 नवम्बर से 27 नवम्बर 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 14 | अंक-120 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की की शताब्दी वर्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया

'भारत 2047' थीम पर उद्योग जगत से भारत फर्स्ट का आह्वान; आत्मनिर्भरता और सुधारों पर जोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन फिक्की के शताब्दी वर्ष का हिस्सा है और इसकी थीम 'भारत 2047' है।

सम्मेलन में 2,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें उद्योग नेता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजदूत और नीति निर्माता शामिल थे। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और अप्रैल 2027 में यह 100 वर्ष पूरे कर रही है। आज यह 2.5 लाख से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विकास गाथा नए अवसर पैदा कर रही है और उद्योग को इन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अगले 20 वर्षों के लिए हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में 'इंडिया फर्स्ट' को आधार बनाने का आह्वान किया। इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और कारोबार को नए अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार आराम का क्षेत्र न बने, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आत्मविश्वास दे। उद्योग से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारी निवेश करने तथा और सुधारों के सुझाव देने को कहा। पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और कॉर्पोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने जैसे कदमों का जिक्र किया।

यह आयोजन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। फिक्की उद्योग और सरकार के बीच संवाद का प्रमुख मंच है। शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री का संबोधन आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और 2047 के विजन को मजबूत करता है। इससे निजी क्षेत्र को निवेश, निर्यात और सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत मिलता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी है।



सीएम मोहन यादव ने गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज की इकाई का किया शुभारंभ

1,920 मेगावाट की एशिया की बड़ी परियोजना; ₹11,474 करोड़ का निवेश, पीक ऑवर्स में तुरंत बिजली उपलब्ध होगी

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के रामपुर में ग्रीनको ग्रुप की गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की एक इकाई का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गांधीसागर में आयोजित नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान हुआ।

परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट है और इसकी लागत ₹11,474 करोड़ है। इसमें नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं सात 240 मेगावाट की और दो 120-120 मेगावाट की। यह पूरी क्षमता पर करीब छह घंटे तक लगातार बिजली पैदा कर सकती है और सालाना लगभग 3,580 मिलियन यूनिट उत्पादन की क्षमता रखती है। करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रही यह इकाई मंदसौर के 765/400 केवी सबस्टेशन से जुड़ी है।

यह पम्प्ड स्टोरेज तकनीक पर आधारित है। ऊपरी जलाशय से पानी छोड़कर टर्बाइन घुमाई जाती है और अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से पानी को वापस ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। पीक घंटों में करीब 2,000 मेगावाट बिजली तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिजली उत्पादन में नई तकनीक है और एशिया महाद्वीप की अपनी तरह की पहली स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सहारा मिलेगा। निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला है और संचालन के बाद भी स्थानीय स्तर पर रोजगार बना रहेगा।

परियोजना का पहला टर्बाइन सेट दिसंबर 2026 से काम शुरू करने का लक्ष्य है और जून 2027 तक पूर्ण व्यावसायिक संचालन की योजना है। यह राज्य के बढ़ते बिजली मांग को पूरा करने और ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।





सोने की कीमत 25% गिरी, गोल्ड लोन कंपनियों को डिफॉल्ट का खतरा

कर्जदार नुकसान न होने से चुकाने से बच सकते हैं; जनवरी-मार्च तिमाही में एनपीए बढ़ने की आशंका

नई दिल्ली: सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर से करीब 25 प्रतिशत गिरने के बाद गोल्ड लोन कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। कर्ज बांटने से ज्यादा कर्जदारों पर नजर रखने की जरूरत पड़ रही है।

आईसीआरए रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.एम. कार्तिक का कहना है कि सोने की कीमत में गिरावट जारी रही तो कंपनियां जोखिम में आ सकती हैं। जब सोना गिरता है तो कर्जदार सोचते हैं कि गिरवी रखा सोना बेचने पर भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए वे लोन चुकाने से बच सकते हैं।

जनवरी-मार्च तिमाही में बड़े लोन पर सोने के दाम 25 प्रतिशत घटने का असर साफ दिखेगा। मन लॉजिक के अनुसार, ₹1 लाख के सोने पर लिए गए ₹75,000 के लोन पर कीमत गिरने से मार्जिन दबाव में आ गया। कीमत गिरने से कर्जदारों के चुकाने की प्रवृत्ति कमजोर होती है और 30-90 दिन के डिफॉल्ट बढ़ते हैं।

2013 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। उस साल सोने की कीमत में तेज गिरावट के बाद मणप्पुरम का सकल एनपीए 14 प्रतिशत तक पहुंच गया और एयूएम ₹9,750 करोड़ पर सिमट गया। 2014 में 2 प्रतिशत तक गिरने के बाद स्थिति सामान्य हुई थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां ऑक्शन की प्रक्रिया तेज कर रही हैं, लेकिन कीमत गिरने से ऑक्शन में नुकसान उठाने का खतरा भी है। कुछ मामलों में 30-90 दिन की चूक और नीलामी बढ़ने की आशंका है। गोल्ड लोन सेगमेंट में अब कीमत स्थिरता और कर्जदारों की चुकौती प्रवृत्ति पर नजर बनी हुई है।



Gadkari Clears ₹1,483 Crore Road Projects on Delhi-Agra Corridor and West Delhi

Three ROBs, Four Flyovers and Underpasses for High-Traffic Stretch; 12.4-km Upgrade for West Delhi

New Delhi: Union Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari has approved road projects worth ₹1,123.56 crore on the Delhi-Agra corridor and ₹359.63 crore for West Delhi.

The Delhi-Agra project covers National Highways 44 and 19 across Faridabad and Palwal districts in Haryana and Mathura and Agra districts in Uttar Pradesh. It includes construction of three road over bridges (ROBs), four flyovers and four vehicle underpasses (VUPs).

The corridor handles about 68,000 passenger car units daily, covering freight, industrial, commuter and tourist traffic. The ROBs will remove delays at railway crossings and ease congestion and safety issues at existing bridges and at-grade intersections. Grade-separated structures along with service roads will separate local traffic from through traffic, reduce conflict points and improve road safety.

The West Delhi project covers a 12.4-km stretch from Industry Nagar Metro Station to Tikri Border. It will benefit areas including Peeragarhi, Nangloi Chowk, Mundka and Ghevra Chowk, and improve connectivity for commuters between Delhi and Bahadurgarh. The works include a concrete road, upgraded service roads and improved junctions to ease congestion, enhance safety and facilitate trade between Delhi and Haryana.

Gadkari announced the approvals on X, highlighting the expected reduction in delays and better safety. Delhi Chief Minister Rekha Gupta thanked him for the West Delhi project, noting its benefits for local areas and cross-state movement.

LTCG and STT Cuts Top Capital Market Wishlist for Budget 2027-28

Stakeholders Seek Tax Relief from Finance Minister; Mutual Funds Demand Debt-Equity Parity

New Delhi: Lowering long-term capital gains (LTCG) tax and securities transaction tax (STT) topped the demands of capital market stakeholders during pre-budget consultations with Finance Minister Nirmala Sitharaman for Union Budget 2027-28.

The fifth consultation in New Delhi involved participants from capital markets, banking, financial services, insurance, mutual funds and NBFCs. Industry associations earlier asked the government to restore the LTCG tax exemption on listed securities that existed before the tax was reintroduced.



Mutual fund representatives sought parity in tax treatment between debt and equity funds. The Finance Industry Development Council (FIDC) proposed a dedicated refinance fund from banks' priority sector lending shortfall for small and medium NBFCs. It also sought exemption of NBFCs from TDS on interest payments under Section 194A, similar to banks, to reduce compliance burden on MSMEs and improve credit flow. Other suggestions included tax relief to make fixed deposits more attractive and addressing issues around insurance commissions amid low penetration.

Stakeholders said lower taxes would boost market liquidity and encourage long-term investment. No specific response from the finance minister was reported. The meetings are part of the government's process to collect inputs ahead of the budget.

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को मिली रफ्तार, 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट

170 एकड़ में टेलीकॉम उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग; पहले चरण में 5,500 करोड़ निवेश और करीब 20,000 रोजगार की संभावना

भोपाल: दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश करने वाली 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट वितरित किए। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया मौजूद रहे। इस मौके पर जोन के दूसरे चरण की घोषणा भी हुई।

मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं में वैश्विक लीडर बन चुका है, अब समय है कि हम सेवा राष्ट्र से उत्पाद राष्ट्र बनें। उन्होंने प्रधानमंत्री की दृष्टि का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय भारत दुनिया पर निर्भर था, आज आत्मनिर्भर है और आने वाले दशक में दुनिया भारत पर निर्भर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भारत का समय है और मध्य प्रदेश का भी।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार टेलीकॉम सेक्टर के लिए समर्पित जोन बनाया गया है। यह केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करने का उदाहरण है। जोन के लिए कैबिनेट से 170 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई है।

ग्वालियर टीएमजेड करीब 170 एकड़ में फैला एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर होगा। यहां टेलीकॉम उपकरण, कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा।



जोन अनुसंधान, विकास और नवाचार पर भी ध्यान देगा। पहले दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में निवेशक आउटरीच कार्यक्रमों से करीब 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धताएं मिली थीं, जिनसे करीब 20,000 रोजगार बनने की संभावना है। जोन आत्मनिर्भर भारत और "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" की दृष्टि से जुड़ा है। लक्ष्य घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करना, आयात निर्भरता घटाना, स्वदेशी अनुसंधान और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और भारत को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का विश्वसनीय वैश्विक गंतव्य बनाना है।

लेटर ऑफ इंटेंट वितरण निवेशकों की दिलचस्पी को जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग अवसरों में बदलने की दिशा में एक कदम है। यह केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी को दर्शाता है। ग्वालियर टीएमजेड भारत को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और तकनीकी प्रगति का वैश्विक केंद्र बनाने में योगदान देने की स्थिति में है। निवेशकों के लिए यह प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और राज्य की प्रोत्साहन नीतियों के साथ टेलीकॉम वैल्यू चेन में प्रवेश का अवसर है।






Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor
7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com


Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor
7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com

IRDAI Warns Insurers on AI Risks as 85% Adopt the Technology

Chairman Ajay Seth questions whether models are trained for Indian conditions and if humans still control key decisions

Mumbai: Nearly 85 per cent of insurance companies in India are already using artificial intelligence in one form or another, but the technology must be trained for local conditions and humans must retain control over critical decisions, Insurance Regulatory and Development Authority of India Chairman Ajay Seth said at the Gatekeepers of Governance event in Mumbai.

"Almost 85% of insurance companies are using artificial intelligence in one form or the other. It is no longer a small proportion," Seth said. He flagged risks in the use of AI for underwriting and claims settlement, asking whether models were adequately trained to reflect India's economy, policyholder behaviour and associated risks. "Are those models trained enough for our economy, our behavior of the policyholders, and the associated risks? Are humans in charge of taking the final decision?" he said.

Seth noted that technology was improving efficiency and enabling innovation even as it created new risks. He also highlighted potential conflicts of interest in distribution, such as lenders selling insurance and motor dealers selling policies while also providing repair services. "The role of the board becomes more important, that what kind of a guardrail it sets to take care that those conflicts of interest do not come in the way of providing the best advice, best service, best product to the customers," he said. Boards, he added, must act as the first line of oversight.

The regulator's role, Seth said, lies in discerning market shifts and risks to outcomes that include policyholder interests, the sustainability of insurers and distributors, and the wider economy. He cautioned against relying solely on historical data amid growing geopolitical and economic uncertainty. "We can no longer afford to merely project the past for the future," he said.

Seth also stressed the need for affordable insurance products, more transparent
accounting practices and a risk-based capital framework aligned with the transition to Indian Accounting Standards. IRDAI is working on a Public Insurance Registry, drawing on data infrastructure already in place in banking and capital markets, to strengthen the sector's data ecosystem. For insurers and investors, the message is clear: AI adoption is widespread, but model fitness for Indian conditions and human oversight will remain under regulatory scrutiny.



क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455 करोड़ का आईपीओ, प्राइस बैंड 259-272 रुपये

फ्रेश इश्यू 355 करोड़ और ओएफएस 101 करोड़; 18-20 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन, 26 नवंबर को लिस्टिंग

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का 455.49 करोड़ रुपये का मुख्य बोर्ड आईपीओ 18 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक खुला है। इश्यू प्राइस बैंड 259 से 272 रुपये प्रति शेयर तय है। लॉट साइज 55 शेयरों का है, जिससे रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम आवेदन राशि ऊपरी बैंड पर 14,960 रुपये बनती है। शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे। अस्थायी लिस्टिंग तिथि 26 नवंबर है।

कुल इश्यू में 1.31 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू (354.77 करोड़ रुपये) और 37.03 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (100.71 करोड़ रुपये) शामिल है। शुद्ध ऑफर का 50 प्रतिशत क्यूआईबी, 15 प्रतिशत एनआईआई और 35 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। एंकर निवेशकों से 17 नवंबर को 135.96 करोड़ रुपये जुटाए गए। बुक रनिंग लीड मैनेजर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज है और रजिस्ट्रार एमयूएफजी इनटाइम इंडिया है।

1994 में स्थापित क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रोकेमिकल्स और बीजों में काम करती है।

पोर्टफोलियो में हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के साथ बायो-स्टिमुलेंट्स, बायो-प्रोटेक्टेंट्स और तरल उर्वरक शामिल हैं। कंपनी फील्ड क्रॉप्स, सब्जियों और फूलों के बीज भी बेचती है। जून 2026 तक 63 पीवीपी रजिस्ट्रेशन और 275 से अधिक हाइब्रिड बीज थे। देशभर में 23 राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में 14,717 स्वतंत्र वितरक और 36 वितरण केंद्र हैं।



वित्त वर्ष 2026 में कुल आय 3,181 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत अधिक थी। शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत बढ़कर 145 करोड़ रुपये हुआ। जून 2026 तिमाही में आय 1,209 करोड़ और लाभ 136 करोड़ रुपये रहा। ऊपरी बैंड पर पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप करीब 4,438 करोड़ रुपये बनती है। फ्रेश इश्यू से प्राप्त धन का मुख्य उपयोग कंपनी और सहायक कंपनी सफायर क्रॉप साइंस के कुछ उधार चुकाने में होगा। करीब 248 करोड़ कंपनी के उधार और 22 करोड़ सहायक कंपनी के लिए आवंटित हैं। शेष राशि अकार्बनिक वृद्धि और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखी गई है। निवेशकों के लिए यह कृषि समाधान कंपनी का मुख्य बोर्ड प्रवेश है। मूल्यांकन, ऋण घटाने की योजना और बीज व क्रॉप प्रोटेक्शन दोनों खंडों की वृद्धि पर नजर रहेगी। लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन बाजार की मांग और कंपनी की क्रियान्वयन क्षमता पर निर्भर करेगा।

Motilal Oswal Alternates Aims to Raise Over ₹3,000 Crore for Office Real Estate Fund

First commercial real estate fund to back early-stage Grade A offices in six tier-I cities through equity JVs with developers

New Delhi: Motilal Oswal Alternates, the alternative investments arm of the Motilal Oswal Group, is targeting over ₹3,000 crore for its first fund dedicated to Indian commercial real estate. The India Assets Excellence Fund – I (IAEF I) will focus on early-stage investments in large-scale Grade A office developments at a time when demand for institutional-grade office space continues to outpace new supply in major markets.

The fund will partner with established developers through equity joint-venture structures across six tier-I cities: Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, National Capital Region, Pune and Chennai. Registered as a Category II Alternative Investment Fund, it will have an eight-year tenure. The sponsor and employees will together commit ₹200 crore, aligning their interests with investors. The total corpus includes a green-shoe option of ₹1,500 crore.

Saurabh Rathi, MD and co-head of Real Estate Funds at MO Alternates, said the fundamentals of Indian office real estate have rarely been stronger and the sector is entering a phase of structural growth, yet institutional capital at the early stage remains scarce. Anand Lakhotia, managing director and co-head, said the fund will open Grade A office development to domestic capital by entering early through structured equity and participating in value creation as projects move from land and approvals through construction to leased, stabilised assets with clear routes to institutional monetisation. The aim is to give investors exposure across the full development cycle.

MO Alternates expects the first close of IAEF I by the end of the first quarter of 2027 and aims to complete fundraising within the following 12 months. Grade A office stock across India's top cities is projected to reach around 1 billion sq ft in the coming quarters, driven by global capability centres, flexible workspace operators, BFSI companies and technology occupiers. Net absorption has exceeded new supply for several quarters, and overall vacancy has fallen to around 15%, with core micro-markets in low single digits.

Despite these conditions, institutional capital remains concentrated in completed, income-producing assets. Early-stage development projects have limited access to institutional equity even though a substantial part of value creation occurs during development and leasing. The new fund seeks to address that gap. For investors, it offers a structured way into the development phase of Grade A offices rather than only stabilised assets, with returns tied to successful leasing and eventual institutional exits.

motilal oswal
Alternates

टाटा स्टील ओडिशा में स्टील प्लांट गैसों से हाइड्रोजन बनाएगी, अमेरिकी फर्म से साझेदारी

कलिंगनगर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट; H2Gen तकनीक से ऑफ-गैसों का उपयोग, 2045 नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में कदम

नई दिल्ली: टाटा स्टील अमेरिकी कंपनी यूटिलिटी ग्लोबल के साथ मिलकर ओडिशा के कलिंगनगर संयंत्र में स्टील निर्माण के दौरान निकलने वाली गैसों से उच्च शुद्धता वाला हाइड्रोजन बनाने की योजना बना रही है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल बताई जा रही है। प्रस्तावित सुविधा की क्षमता 10 टन प्रतिदिन होगी और इसमें ह्यूस्टन स्थित यूटिलिटी ग्लोबल की H2Gen तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह तकनीक ब्लास्ट फर्नेस गैस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BOF) गैस के मिश्रण से हाइड्रोजन बनाती है।

दोनों कंपनियां पहले संयुक्त फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन (FEED) अध्ययन करेंगी। इन अध्ययनों के आधार पर टाटा स्टील के बोर्ड द्वारा फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन (FID) लिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद संयंत्र की स्थापना और संचालन कलिंगनगर में होगा। यूटिलिटी ग्लोबल ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया विकसित की है जो कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त स्टील प्लांट गैसों से हाइड्रोजन बनाती है। इस तकनीक का कनाडा के एक स्टील उत्पादक के ब्लास्ट फर्नेस प्लांट में वास्तविक ब्लास्ट फर्नेस गैस पर प्रदर्शन हो चुका है।

प्रस्तावित सुविधा यूटिलिटी ग्लोबल की अब तक घोषित सबसे बड़ी औद्योगिक H2Gen तैनाती और भारत में पहली परियोजना होगी। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (टेक्नोलॉजी, आरएंडडी, न्यू मटेरियल्स बिजनेस एंड ग्राफीन) सुबोध पांडेय ने कहा कि किसी तकनीक को स्टील डिकार्बोनाइजेशन में सार्थक योगदान देने के लिए उसे चालू स्टील प्लांट के पैमाने और जटिलता पर काम करना होगा। H2Gen जैसी तकनीकें मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए उत्सर्जन कम करने का अवसर देती हैं। यह सहयोग कंपनी की गहरी परिचालन डिकार्बोनाइजेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

परियोजना मौजूदा संयंत्र बुनियादी ढांचे का उपयोग करके उत्सर्जन घटाने का रास्ता तलाशती है। स्टील प्लांट ऑफ-गैसों में बची अवशिष्ट ऊर्जा को बिजली का उपयोग किए बिना पानी से हाइड्रोजन बनाने में लगाया जाएगा। उत्पादित हाइड्रोजन को ब्लास्ट फर्नेस में इंजेक्ट करके कार्बन-सघन ईंधन का एक हिस्सा बदलने की कल्पना की गई है। इससे आयरनमेकिंग प्रक्रिया का उत्सर्जन कम हो सकता है और संयंत्र के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आने की उम्मीद है।

यह पहल टाटा स्टील के लो-कार्बन स्टीलमेकिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा है और 2045 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करती है। टाटा स्टील समूह की वार्षिक क्रूड स्टील क्षमता 36 मिलियन टन है। निवेशकों के लिए यह दिखाता है कि कंपनी पारंपरिक स्टीलमेकिंग को पूरी तरह बदले बिना ऑफ-गैसों से मूल्य निकालने और उत्सर्जन कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सफलता FEED अध्ययन के परिणाम, बोर्ड की मंजूरी, स्थानीय अनुमोदन



अदाणी एनर्जी ने बिहार में ₹500 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया

पीरपैंती प्लांट से 2,400 मेगावाट बिजली निकासी; 2028 की आखिरी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य

नई दिल्ली: अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (एईएसएल) ने बिहार में पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए मिला यह प्रोजेक्ट चालू होने के बाद सालाना करीब ₹500 करोड़ का टैरिफ देगा।

प्रोजेक्ट का नाम "एवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम 3X800 मेगावाट एसटीपीपी पीरपैंती" है। इसे स्पेशल पर्पज व्हीकल विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के जरिए लागू किया जाएगा। लक्ष्य 2028 की चौथी तिमाही तक पूरा करना है।

इसमें 881 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 3,160 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ी जाएगी। चार गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन झंझारपुर, बेथौली और बेगूसराय में बनाए जाएंगे। साथ ही पीरपैंती-झंझारपुर, पीरपैंती-बेगूसराय और बेगूसराय-बख्तियारपुर जैसी 400 केवी डबल सर्किट लाइनें भी शामिल हैं।

एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा कि पीरपैंती ट्रांसमिशन योजना 2,400 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिए मजबूत निकासी प्रणाली बनाएगी और बिहार के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगी। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी और राज्य की बढ़ती बिजली मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।

प्रोजेक्ट पूरा होने पर एईएसएल का ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 1,46,585 एमवीए हो जाएगी। कंपनी का ट्रांसमिशन कैपेक्स करीब ₹91,500 करोड़ पहुंच जाएगा। यह अदाणी पावर के प्रस्तावित 2,400 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्लांट से बिजली निकालने और बिहार में आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।



Cyient Semiconductors Secures $10 Million from Global Foundries

US Chipmaker Invests at $510 Million Valuation; Funds to Expand Custom ASIC Capabilities

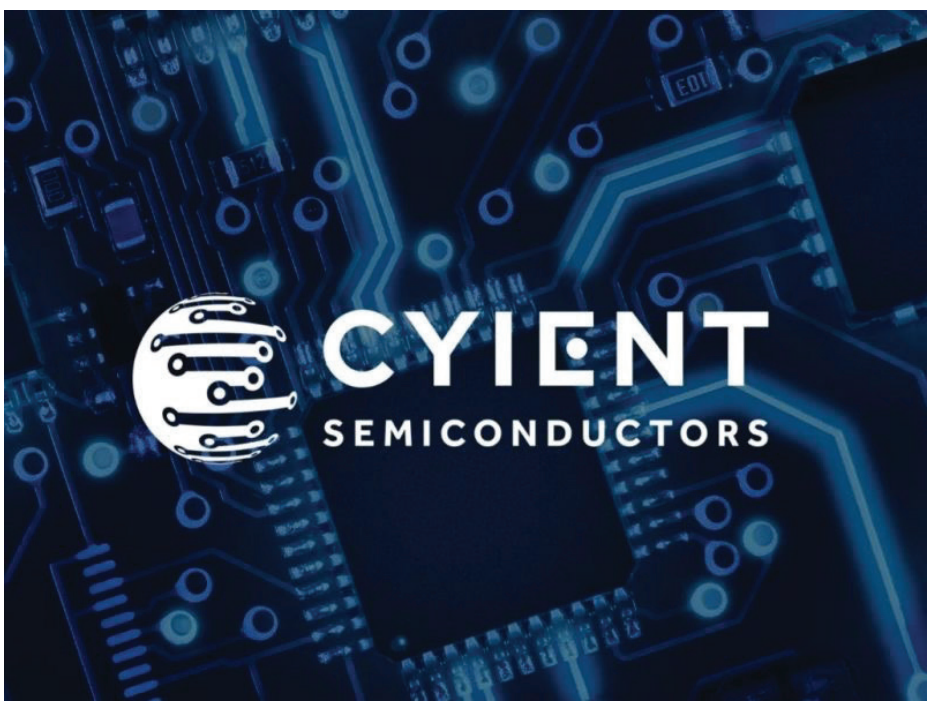
Hyderabad: Cyient Semiconductors has approved a $10 million strategic equity investment from US-based chipmaker GlobalFoundries. The investment is at a pre-money valuation of $490 million, taking the post-money equity valuation to $510 million.

The valuation matches the recent funding round led by Edelweiss (EAAA India Alternatives). GlobalFoundries will subscribe to fully and compulsorily convertible cumulative preference shares.

The funds will be used to expand turnkey custom application-specific integrated circuit (ASIC) capabilities, accelerate custom silicon development, strengthen long-term wafer supply assurance and improve supply chain resilience. It will also help the company scale engineering operations and support global customer engagements.

Cyient Semiconductors is the Hyderabad-headquartered custom silicon arm of Cyient Limited. It offers custom ASIC and application-specific standard product solutions with a focus on analog mixed-signal, intelligent power and advanced platforms. The company serves automotive, industrial, AI, communications and data centre markets, and operates design centres in India, Belgium and the US.

CEO Suman Narayan said the investment validates the company's vision and the opportunity for semiconductor innovation from India. "Having a leading semiconductor ecosystem partner as a strategic investor accelerates our access to advanced manufacturing capabilities and strengthens our ability to deliver custom silicon and power products globally," he said. The partnership is expected to bolster Cyient Semiconductors' position in the global custom silicon market while supporting India's semiconductor ecosystem. The announcement was made through a regulatory filing.



Urban Company Raises ₹2,500 Crore via QIP at ₹156 a Share

Funds to Back InstaHelp Expansion, Marketing and Technology; Shares Allotted at 3% Discount

Mumbai: Home services platform Urban Company has raised ₹2,500 crore through a qualified institutional placement (QIP) from institutional investors. The company allotted shares at ₹156 apiece, a 3 per cent discount to the floor price of ₹161.03 and an 11 per cent discount to Thursday's closing price of ₹175.75.

The Fund Raise Committee approved the allotment of about 16.02 crore equity shares. Following the issue, the company's paid-up equity share capital has risen from ₹1,542.18 crore to ₹1,702.44 crore, and the number of outstanding shares has increased from 154.21 crore to 170.24 crore.

Of the proceeds, ₹600 crore has been earmarked for the InstaHelp business, which operates in the 10-minute house-help segment. Another ₹540 crore will go towards marketing initiatives, while ₹200 crore is allocated for technology development and cloud infrastructure.

Urban Company, which was named Startup of the Year at the ET Startup Awards 2025, said the capital will provide flexibility to invest across its core India business, international operations and Native brand, while also supporting selective inorganic opportunities. The company went public in September 2025, raising ₹472 crore through its IPO.

The QIP opened on 16 November and closed on 19 November 2026. The fresh capital comes as the company continues to scale multiple business lines after listing.

बिजनिस ने नाम बदला, अब ज़ोरिट; ₹27 करोड़ जुटाए!

स्पैरो कैपिटल की अगुआई में फंडिंग; ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए 60 मिनट में B2B डिलीवरी का लक्ष्य

बेंगलुरु: B2B कॉमर्स स्टार्टअप बिजनिस ने अपना नाम बदलकर ज़ोरिट कर लिया है और स्पैरो कैपिटल की अगुआई में ₹27 करोड़ का फंडिंग राउंड पूरा किया है। मौजूदा निवेशकों इंफो एज और वाटरब्रिज ने ₹5-5 करोड़ लगाए, जबकि बेटर कैपिटल ने भी भाग लिया।

एंजेल निवेशकों में अनुपम मित्तल, शिपरॉकेट के संस्थापक, एक्सप्रेसबीज के मोहित सरदाना और सॉफ्टबैंक के सार्थक मिश्रा शामिल हैं।

कंपनी की स्थापना 2015 में सिद्धार्थ विज, चैतन्य राठी, सिद्धार्थ रस्तोगी और सचिन चौहान ने की थी। पहले यह मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को जोड़ने वाला B2B मार्केटप्लेस था। 2024 के अंत में इसने डार्क स्टोर्स और खुद के इन्वेंटरी वाले क्विक कॉमर्स मॉडल पर शिफ्ट किया। अब ऑफलाइन रिटेलर्स स्थानीय डार्क स्टोर्स से सामान ऑर्डर करते हैं और 60 मिनट में डिलीवरी मिलती है। ज़ोरिट के पास अक्टूबर 2026 तक 12-15 डार्क स्टोर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 600 से ज्यादा फैक्ट्रियां जुड़ी हैं। सालाना बिक्री ₹120 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। करीब आधे डार्क स्टोर्स ब्रेक-ईवन पर हैं।

नई फंडिंग का इस्तेमाल क्विक कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने और रिटेलर्स के साथ गहरा जुड़ाव बनाने में किया जाएगा। सह-संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ विज के अनुसार, ज़ोरिट इस्तेमाल करने वाले करीब 60 प्रतिशत रिटेलर्स पहले कभी ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते थे। मासिक ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी पांच गुना बढ़ी है और छठे महीने के बाद रिटेंशन चार गुना सुधरी है।



Cashify Turns Profitable in FY26 with ₹6.5 Crore Net Profit

Revenue Rises 50% to ₹1,641 Crore on Strong Demand for Refurbished Electronics

Bengaluru: Recommerce platform Cashify reported a consolidated net profit of ₹6.5 crore in FY26, reversing a net loss of ₹10.6 crore in the previous financial year. Revenue from operations grew 50 per cent year-on-year to ₹1,641.2 crore.

The turnaround was driven by higher demand for refurbished smartphones, laptops and other electronics. EBITDA rose to ₹22.7 crore from about ₹2 crore in the preceding year, reflecting improved operating performance.

Cashify facilitates the buying, selling and refurbishment of pre-owned electronic devices. The company said it plans to expand its refurbishment network and offline presence to support further growth. It currently operates more than 250 branded stores across 95 cities.Total expenses increased 45.7 per cent during the year, slower than the 50 per cent revenue growth. Employee expenses as a percentage of revenue declined to 9 per cent from 10.5 per cent. The improvement in profitability came despite a drop in other income.

The results come as India's refurbished electronics market sees growing participation from consumers looking to sell used devices and buy pre-owned products. Cashify's FY26 performance reflects both higher volumes in its core recommerce business and a tighter cost structure after years of losses.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25800	26692	26250	26025	25583	25358	24916	24691
BANK NIFTY	64635	69264	66970	65802	63508	62340	60046	58878
SENSEX	83920	86988	85511	84716	83239	82444	80967	80172
FINNIFTY	28871	30248	29573	29222	28547	28196	27521	27170
MIDCAP	14305	14826	14620	14463	14257	14100	13894	13737
ACC	1282	1382	1334	1308	1260	1234	1186	1160
AXISBANK	1448	1601	1525	1486	1410	1371	1295	1256
ABCAPITAL	420	449	436	428	415	407	394	386
BHARTIARTL	2150	2224	2198	2174	2148	2124	2098	2074
BHEL	434	462	450	442	430	422	410	402
BIOCON	364	380	374	369	363	358	352	347
BEL	401	418	411	406	399	394	387	382
CDSL	1430	1552	1516	1473	1437	1394	1358	1315
DATAPATTERN	4215	4580	4437	4326	4183	4072	3929	3818
ESCORTS	2475	2629	2552	2514	2437	2399	2322	2284
EICHERMOTOR	8104	8939	8544	8324	7929	7709	7314	7094
FEDERALBANK	373	396	385	379	368	362	351	345
GRINFRAPOJECT	769	867	841	805	779	743	717	681
HDFCBANK	849	913	882	865	834	817	786	769
HCLTECH	1341	1480	1440	1390	1350	1300	1260	1210
HINDUNILVR	2055	2191	2133	2094	2036	1997	1939	1900
HAL	4790	5053	4942	4866	4755	4679	4568	4492
HYUNDAI	2212	2468	2357	2285	2174	2102	1991	1919
IOC	150	161	155	153	147	145	139	137
ICICIBANK	1641	1733	1689	1665	1621	1597	1553	1529
INFY	1093	1231	1196	1144	1109	1057	1022	970
ITC	299	268	285	250	267	232	249	214
KOTAKBNK	514	552	535	524	507	496	479	468
LICHOUSING	612	672	649	630	607	588	565	546
LT	4199	4340	4277	4238	4175	4136	4073	4034
LUPIN	1998	2092	2052	2025	1985	1958	1918	1891
MARUTI	13983	16007	15023	14503	13519	12999	12015	11495
M&M	3548	3896	3733	3640	3477	3384	3221	3128
MGL	1113	1225	1192	1153	1120	1081	1048	1009
MAZGAONDOC	1844	1973	1937	1890	1854	1807	1771	1724
PFC	331	357	348	339	330	321	312	303
RECLTD	298	319	311	305	297	291	283	277
RELIANCE	1378	1445	1414	1396	1365	1347	1316	1298
SBIN	1170	1296	1235	1203	1142	1110	1049	1017
SUNPHARMA	1892	1977	1946	1919	1888	1861	1830	1803
SHRIRAMFINANCE	966	1037	1017	991	971	945	925	899
TITAN	4613	5274	5106	4860	4692	4446	4278	4032
TCS	2380	2566	2508	2444	2386	2322	2264	2200
TATAMOTORS	266	296	285	275	264	254	243	233
UPL	569	626	602	585	561	544	520	503
VALIENT	322	388	375	348	335	308	295	268
WIPRO	185	213	206	195	188	177	170	159

Adani Begins Production of India's Longest 91.2-Metre Wind Turbine Blades

New Delhi: Adani New Industries Ltd (ANIL), a subsidiary of Adani Enterprises, has started manufacturing India's longest onshore wind turbine blades at its Mundra facility in Gujarat. The blades measure 91.2 metres and are designed for the MWL185-5.0 MW platform.

The turbine has a rotor diameter of 185 metres and a hub height of 140 metres, with a swept area of nearly 26,600 square metres. The platform has been certified by German body WindGuard Certification GmbH after prototype testing at Mundra, clearing the way for serial production under IEC 61400 standards.

The larger blades are designed to capture more wind energy, including at sites with low and moderate wind speeds, thereby expanding the geographical range suitable for commercial wind power. The Mundra plant already produces blades of 78.6 metres and 80.5 metres.

Adani Wind CEO Milind Kulkarni said producing India's longest blade and securing certification for the 5 MW platform is an important milestone for the company and the country's wind manufacturing sector. Larger blades and higher-capacity turbines help broaden the potential for wind generation.

The Mundra facility currently has a manufacturing capacity of 2.25 GW, with further expansion planned. Adani Wind has three turbine platforms on the Ministry of New and Renewable Energy's Approved List.

The development supports India's push to strengthen domestic renewable energy manufacturing and reduce equipment imports.

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in